

भारतीय समाज की विघटनकारी शक्तियाँ (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ० गौतम बनर्जी

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (बिजनौर)

ईमेल: banerjee.gautam609@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत लेख में वर्तमान भारतीय समाज में प्रभावी होती विघटनकारी शक्तियों, उनके प्रभावों तथा इन्हें प्रभावहीन करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। स्वतंत्रोपरांत आधुनिक भारत में क्षेत्रवपाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था आदि की आड़ में विघटनकारी शक्ति ने भारत की एकता एवं अखंडता को बहुत चोट पहुँचाई है। वहीं सामाजिक भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी, बेरोगारी, असमानता, नित्य बदलते सामाजिक मूल्य जो आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण उत्पन्न हुए हैं। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विघटन के लिए उत्तरदायी हैं। यदि हमें मानवीय पीड़ा और समाज की विघटनकारी शक्तियों को प्रभावहीन करना है तो मानव, मानवीय मूल्य एवं नैतिक उत्थान पर आधारित विकास और प्रगति के आदर्श मानदण्ड निर्धारित करने होंगे तथा भारतीय आध्यात्म एवं सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना होगा।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
निम्न प्रकार है:

डॉ० गौतम बनर्जी

भारतीय समाज की
विघटनकारी शक्तियाँ
(एक समाजशास्त्रीय
अध्ययन)

शोध मंथन, जून 2018,
पेज सं० 164-168

Article No. 25

[http://
anubooks.com?page_id=581](http://anubooks.com?page_id=581)

भारतीय समाज की विघटनकारी शक्तियाँ

समाज कोई अखण्ड व्यवस्था नहीं है। वास्तव में समाज तो अनेक क्रियाशील इकाइयों परिवारों, संस्थाओं का व्यवस्थित रूप है। यही इकाइयाँ अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए समाज को संगठित रखने का प्रयास करती हैं, लेकिन कोई भी समाज सम्पूर्ण रूप में कभी भी संतुलित या संगठित नहीं रहता है। समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियाँ भी सतत क्रियाशील रहती हैं जिनके कारण कुछ न कुछ अव्यवस्था या असंतुलन की स्थिति भी बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में विघटनकारी ताकतों का स्वरूप एक प्रक्रिया के रूप में क्रियाशील रहकर आगे बढ़ता है या पीछे भी हटता रहता है।

गतिशील समाज में सामाजिक संरचना में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, अचानक ही नयी परिस्थितियाँ और नयी आवश्यकताएँ व्यक्ति के समक्ष खड़ी हो जाती हैं। स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति इनसे अनुकूलन नहीं कर पाता है। तो विघटनकारी ताकतें प्रभावी हो जाती हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति की मनोवृत्ति व सामाजिक मूल्य विरोधाभास लिए हुए हैं, सोच का दायरा संकीर्ण हो रहा है, परिवार विवाह जैसी संस्थाएँ विकृत हो रही हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसी विषम स्थिति में व्यक्ति भ्रमित है, वहीं विघटनकारी ताकतें प्रबल हो रही हैं।

आजादी के बाद समाज में विघटनकारी शक्तियों में तेजी से वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण आधुनिकता, औद्योगीकरण, प्रजातंत्र, नवीन मूल्यों, भौतिक साधनों का प्रभाव आदि तत्वों ने आम भारतीयों की आकांक्षा में व्यापक परिवर्तन किया है। आधुनिक भारत में विघटन के विभिन्न रूप पारिवारिक, आर्थिक, जातीय, धार्मिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्रवाद, भाषावाद, वर्णव्यवस्था आदि की आड़ में विघटनकारी ताकतों ने भारत की एकता व अखण्डता को बहुत क्षति पहुँचायी है। सामाजिक भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, नित्य बदलते सामाजिक मूल्य तथा समाज में गहरे बैठा भ्रष्टाचार, सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक विघटन के लिए जिम्मेदार है।

वर्तमान में त्याग, सेवा, सद्भाव का स्थान ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्तिवाद आदि ने ले लिया है जिससे समाज में अशांति, उपद्रवों में वृद्धि हुई है, वहीं औद्योगीकरण, अति तकनीकीकरण ने श्रम के अवसर घटाये हैं, श्रमिकों की छटनी से बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, विकास की धीमी प्रगति, दोषपूर्ण शिक्षा से जहाँ अपराध में वृद्धि हुई है, वहीं नैतिक पतन भी हुआ है और चोर बाजारी बढ़ी है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से घिरा है, जिससे उसका मन संस्थान खिन्न व उद्विग्न रहने लगा है, विघटन का आक्रमण हर किसी पर छाया हुआ दिखाई पड़ता है। शांति और संतोष, प्रसन्नता एवं निश्चितता मात्र कहने- सुनने की बात रह गयी है। आज का व्यक्ति मानसिक दृष्टि से अति दुर्बल होता जा रहा है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विवाह विच्छेद, विधवा विवाह पर रोक, धार्मिक कुरीतियों ने परिवार को ही विघटित कर दिया है, पति-पत्नी के संबंध असंतुलित हुए हैं, वहीं व्याभिचार व वैश्यावृत्ति में वृद्धि हुई है, भावात्मक संबंध दब गये हैं। हमारे देश में बलात्कार, गुण्डागर्दी आदि के कारण प्रति घंटे एक हत्या होती है, भयंकर मानसिक संघर्ष की स्थिति ने परिवार में बिखराव ला दिया है। गिलिन के अनुसार, "अब घर केवल पेट भरने और रैन बसेरा करने का स्थान ही रह गया है।"

वर्तमान समय में आर्थिक असमानताओं और उनके राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक हथकंडों ने राष्ट्रीय एकता को बहुत चोट पहुँचायी है, क्षेत्रीयता चरम पर है, हिन्दी एवं अहिन्दी भाषी लोगों के मतभेद, असम में असमियों व बंगालियों में संघर्ष, महाराष्ट्र में शिवसेना का दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध युद्ध सी स्थिति, बिहार जैसे प्रदेशों में निजी सेनाओं का अस्तित्व, हिंसा की कार्यवाहियों ने राष्ट्रीय एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रो. हुमायुँ कबीर के अनुसार, “बगैर किसी शर्त के यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि भारत अनेक रूप है और अनेक रूप रहेगा तो जनता में भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के मार्ग की एक प्रमुख बाधा का निराकरण अपने आप ही हो जायेगा।”

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे संपूर्ण राष्ट्र ही विघटनकारी ताकतों से घिर गया है, देश विरोधी ताकतें बम विस्फोट, ट्रेन दुर्घटनायें, विमान अपहरण, राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश करके देश के गोपनीय दस्तावेज दूसरे राष्ट्र को बेचकर, राष्ट्र की एकता को निर्बल कर रहे हैं। बड़े-बड़े आर्थिक घोटालों के द्वारा देश खोखला हो रहा है, विडम्बना यह है कि इन कार्यों में मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी सभी लिप्त हैं। देश संक्रमणकाल से गुजर रहा है। कश्मीर आये दिन सामूहिक हत्याओं, बम विस्फोटों, पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में ओई.एस.आई. के खतरनाक मंसूबे पूरे हिस्से को अलग करना चाहते हैं। प्रतिबन्धित सशस्त्र संगठन अपहरण, फिरौती, चुनाव, बहिष्कार, इस्लामीकरण की आड़ में मदरसों का जाल फैलाकर आतंकवाद के अड्डे विकसित कर रहे हैं।

“वर्तमान में साम्प्रदायिकता ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वाधिक क्षति पहुँचायी है। साम्प्रदायिकता का आधार केवल धर्म ही नहीं, जाति भी है, जन्म भी है, अर्थ भी है, रंग भी है और राजनीति भी है।

धर्म के आधार पर देश का विभाजन और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे क्षेत्रीयता को बल मिला। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का सरकारों ने क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि “हमारी सरकार क्षेत्रीय लोगों को ही संरक्षण देगी, जो 1970 के बाद आये हैं वे अपना बिस्तर तैयार रखें। क्षेत्रीय भावी सन्तति के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें कोई राष्ट्र विरोधी कहता है तो हम राष्ट्र विरोधी हैं।

राष्ट्रीय विखंडन के लिए समाज में व्याप्त जातीय भेदभाव भी कम उत्तरदायी नहीं रहा है। समाज में घुन की तरह व्याप्त ऊँच-नीच, भेदभाव, छूआछूत जातीयता आदि विघटन के आधार रहे हैं। जाति आधारित राजनीतिक दलों ने इसे और हवा दी है, क्योंकि स्वार्थवश इन दलों ने जातीय वोटों को महत्व दिया है। बिहार में रणवीर सेना, शोषित समाजवादी सेना आदि जातीय सशस्त्र सेनायें आये दिन सामूहिक नरसंहार करती रहती हैं, वहीं प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के समय मंडल आयोग की सिफारिशों से युवा असंतोष भड़का, आरक्षण चुनावी हथकंडा बन गया है। आरक्षण की प्रक्रिया ने समाज में वैमनस्यतास के गहरे बीज बोये हैं। देश की कुल जनसंख्या के 14.16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। इनकी दशा आज भी संतोषजनक नहीं है। इन जातियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण आज भी हो रहा है। जातीयता के विभाजनकारी जहर को क्षेत्रीय दलों, जातीय संगठनों द्वारा आज भी पाला पोषा जा रहा है, जबकि आजादी के बाद प्रगति के दौर में जातीय अभिशाप खत्म होना चाहिए था।

आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कितने आश्चर्य की बात है कि देश भाषा के क्षेत्र में गुलाम ही है। महात्मा गाँधी भी देश में हिन्दी के हिमायती थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि "आजादी के 6 माह बाद यदि कोई संसद या विधानसभा में अंग्रेजी बोलता पाया गया तो मैं उसे गिरफ्तार करवा दूँगा। "दुर्भाग्य से गाँधी जी का विचार गाँधी जी के साथ दफना दिया गया। हम आज तक एक भाषा के माध्यम से अपना राष्ट्रीय स्वरूप नहीं बना पाये हैं।

वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के नाम पर यंत्रिकरण, उपभोक्तावाद को ही प्रगति का पर्याय मान लिया गया है। औद्योगिकीकरण जिस गति से बढ़ा है उसी गति से आर्थिक विषमता भी बढ़ी है। शहरों में एक ओर उद्योगपति हैं तो दूसरी ओर मजदूर वर्ग, नगरों में बड़ी, अट्टालिकाओं के सामने ही झुग्गी झोंपड़ियाँ, भूख और गरीबी से कराहती मानव आत्मायें प्रगति की वर्तमान धारा का उपहास उड़ाती देखी जा सकती है। लगता है पूरा देश इंडिया और भारत में विघटित हो गया है, वर्तमान में गरीबी विघटन के मूल में है, देश में लगभग 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के स्तर से नीचे हैं, उनमें भी 30 करोड़ लगभग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं।

औद्योगिकीकरण ने ही शहरीकरण को विकसित किया है, जिससे आज सभी नगर आवास समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ चिंताजनक हैं। गंदी बस्तियाँ शहरों का विकृत रूप प्रस्तुत कर रही हैं। बम्बई जैसे महानगर में 5.1 प्रतिशत लोगों के पास मकान ही नहीं है। 77.3 प्रतिशत के पास 1 कमरा ही उपलब्ध है। परिवारों में गोपनीय स्थान का अभाव है, जिसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वयं माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे बाहर खेलें। वहीं गाँवों से मजदूर भी वहाँ अकेले रहकर नैतिक पतन के शिकार हो जाते हैं। गंदी बस्तियाँ भी मजदूरों को अपराध से जोड़कर विघटित करती है।

नगरों में बच्चे बाल अपराधी बन रहे हैं। देश में इस समय लगभग 89797 बाल अपराधी हैं जिन्हें अदालत में पेश किया गया है। भारत में लगभग 16000000 बच्चे गंदी बस्तियों में रहते हैं। ये शराब की दुकानों, जुए के अड्डों, वैश्यालयों में बॉय का कार्य करते हैं। यही बाद में विघटनकारी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगरों का अभिशाप वैश्यवृत्ति भी है। आज भी महानगरों में कार्ल गर्ल, सेल्स गर्ल आदि बदले रूपों में वैश्यवृत्ति विद्यमान है। देश में इस समय लगभग 20 लाख 96 हजार वैश्यायें हैं जो कि एक कलंक है।

भौतिक विकास, केन्द्रीय औद्योगिकीकरण एवं अति तकनीकी विकास के कारण आर्थिक लाभ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य बन गया है। समाज का प्रत्येक वर्ग असीम विलासित व सुख साधनों को पाने हेतु नैतिकता को त्यागकर कोई भी रास्ता अपनाए जाने को तैयार है। इसी कारण रिश्वतखोरी, काले धंधे, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार आदि अपराध बढ़ रहे हैं। सारे देश में संगठित गिरोहों द्वारा व्यवसायियों का अधिकारी वर्ग का या इनके बच्चों का अपहरण फिरौती हेतु किया जा रहा है। फिल्म क्षेत्र में भी प्रमुख लोगों से माफिया धन ऐंठ रहे हैं। न देने पर हत्यायें भी की जा रही हैं। बिहार में विधायक, मंत्री स्वयं घोटाले में पकड़े जाने पर जेल भेजे गये हैं। राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित नेताओं वे प्रवर्तन अधिकारी के भ्रष्टाचार में पकड़े जाने पर सफेदपोश अपराध का वीभत्स के रूप सामने आया है।

वर्तमान में नैतिक मूल्य बहुत गिर गये हैं। अनैतिकता के विकास में टी.वी. चलचित्र की महती भूमिका है। फिल्मों में कथानक युवकों को अपराध की ओर मोड़ रहे हैं। वहीं फिल्मों के कामोत्तजक दृश्य, ब्लू फिल्में, असमय ही बच्चों में यौन प्रौढ़ता ला रही है जिससे यौन अपराध बढ़ रहे हैं। टी.वी. ने सामाजिक दायरा संकुचित किया है तथा परिवार के सदस्यों के मध्य होने वाले वार्तालाप के समय को छीन लिया है।

आधुनिकता का वास्तविक प्रभाव प्रेमचन्द्र के गोदान में देखा जा सकता है। देश में आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ ने ही किसानों को मजदूरों में रूपांतरित होने की विवशता दी है। गोदान का नायक परम्परा, धर्म विश्वास, महाजन और मनुष्यता के चक्र में पिसता हुआ अंत में नागरिक सभ्यता के अभिशाप मजदूर के रूप में मरता है। समाज में मानवीय विघटन का यह सजीव दृश्य है।

आर्थिक बदहाली के शिकार, शोषित, प्रताड़ित व्यक्ति मानसिक असंतुलन की स्थिति में आत्महत्याएँ कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रतिदिन लगभग 1000 व्यक्ति आत्महत्या करते हैं जिसमें लगभग 110 व्यक्ति भारत में आत्महत्या का शिकार होते हैं। दिशाहीनता, मानसिक असंतुलन, भविष्य की असुरक्षा आदि के कारण युवा नशे का शिकार हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत युवा एवं 18 प्रतिशत युवतियाँ नशे के आदी हैं। सामाजिक अनुशासन छिप सा गया है। सामाजिक मूल्य टूट रहे हैं। हताशा और निराशा के दौर में विघटनकारी ताकतें बलवती होकर देश विरोधी कार्यों में लिप्त है जिसका परिणाम आज सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के समक्ष है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि हमें मानवीय पीड़ा और समाज की विघटनकारी ताकतों को प्रभावहीन करना है तो हमें विकास और प्रगति के आदर्श मानदण्ड निर्धारित करने होंगे, जिनमें मानव, मानवीय मूल्य नैतिक उत्थान का स्थान सर्वोपरि होगा, भारतीय आध्यात्म, दर्शन व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना होगा। तभी हम भारतीय समाज को आदर्श, सुखमय व जीव्य बना सकते हैं। यही वांछनीय है, यही प्रगति भी है।

संदर्भ

1. गिलिन और गिलिन, 'अप साइट', पेज, 777?
2. बी.पी. पांडेय, 'भारतीय समाज एवं राजनीति', सरस्वती सदन, दिल्ली, पृ. 482
3. राज्यसभा की कार्यवाही, 17 दिसम्बर 1981 प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी का वक्तव्य
4. दि नेशनल गेंग, अप्रैल 1982
5. वेद प्रताप वैदिक, 'अंग्रेजी हटाओं क्यों और कैसे', प्रभात प्रकाशन, चावड़ी बाजार, दिल्ली, पृ. 33
6. गंगा प्रसाद विमल, 'आधुनिकता साहित्य के संदर्भ में', पृ. 97